



## स्रोतों का अधिकतम संभव इस्तेमाल

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को छोड़ने का मतलब है वैकल्पिक ऊर्जा के सभी उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम संभव इस्तेमाल करना, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। इसके लिए नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने होंगे और बड़ी मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

आरती सिंह।।

जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में शुरू हो रही कोप-26 बैठक से ठीक पहले रोम में हुए जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत ने दो टूक बात कही। उसने कहा कि अगर भारत से जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद की जाती है तो न केवल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की सदस्यता देनी होगी बल्कि आवश्यक तकनीक की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। ध्यान रहे, ये दोनों बातें शर्त के रूप में नहीं, बल्कि आवश्यकता के रूप में रखी गई हैं। समझना होगा कि बड़ी-बड़ी बातें करते रहने का कोई खास मतलब नहीं बनता है, अगर उन्हें पूरा करने लायक स्थितियां बनाने की कोशिश न की जाए।

भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए अपनी इच्छा जता चुका है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्तिसंपन्न राष्ट्र के रूप में वह इसका हकदार भी है। बावजूद इसके, चीन के विरोध के चलते यह अटका हुआ है। अब अगर भारत को कोयले का इस्तेमाल कम करते हुए वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा की अपनी जरूरतें पूरी करने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है तो बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा की भी जरूरत होगी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को छोड़ने का मतलब है वैकल्पिक ऊर्जा के सभी उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम संभव इस्तेमाल करना, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। इसके लिए नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने होंगे और बड़ी मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह



कारण एनएसजी की सदस्यता के जरिए ही हो सकता है। यही नहीं, इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और आधुनिकतम तकनीक की भी जरूरत होगी। इन्हीं सबके मद्देनजर भारत ने आगे बढ़ने का एक खास फॉर्म्युला सुझाया है, जिसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कर्षेबिलिटीज (सीबीडीआर-आरसी) कहा गया है। सीधे शब्दों में इसका मतलब सबकी साझा किंतु अलग जिम्मेदारियां और अपनी-अपनी क्षमता को समझते हुए उसके मुताबिक आगे बढ़ने से है। इसी के तहत भारत ने मजबूती से यह बात दोहराई है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए सालाना 100 अरब डॉलर मुहैया

कराने का वादा विकसित देश पूरा नहीं कर पाए हैं और इसे 2023 तक हर हाल में पूरा करना चाहिए। अपने इस साफ और साहसिक स्टैंड के जरिए भारत ने जहां क्लाइमेट चेंज से जुड़े अजेंडे को हवाई बातों से टोस जमीनी हकीकत की ओर मोड़ने का प्रयास किया है, वहीं सारी जिम्मेदारियां विकासशील देशों के सिर डाल देने की जानी-अनजानी कोशिशों की काट भी पेश की है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो जी 20 देशों का यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने की दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ाता नहीं दिख सका, लेकिन भारत का यह स्पष्ट रुख अगर ग्लासगो सम्मेलन की अनिश्चितता दूर करने में मदद करता है तो यह अपने आप में एक उपलब्धि होगी।

## उचित सत्कार

अशोक वोहरा।  
पेड़ पर एक हंस और हंसिनी रहते थे। वे पूर्वजन्म में भी गृहस्थ थे। हंस हंसिनी से बोला, "द्वार पर दो अतिथि आए हैं। उनका उचित सत्कार होना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों को शीत से बचाने का उपक्रम करें क्योंकि आज ठंड बहुत ज्यादा है।" हंसिनी ने पेड़ से सूखी लकड़ियां गिरानी शुरू कर दीं। हंस किसी प्रकार गांव से आग ले आया। योगी ने आग जला दी। फिर पेड़ से गिराए गए फलों को इकट्ठु किया। राजा मांसाहारी था। हंस ने हंसिनी से कहा, "प्रिये, मेरे न रहने पर तुम बच्चों का पालन पोषण कर लोगी, किंतु मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा, इसलिए पेड़ के नीचे जलती आग में गिरकर प्राण दे रहा हूँ, ताकि राजा की भूख शांत हो सके।" यह कहकर हंस आग में गिर पड़ा।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### मौलिक विसंगतियां

हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिस प्रकार चीन ने अमेरिका के साथ जुड़ाव बनाकर अपने को आगे बढ़ा लिया, उसी प्रकार हम भी अपने को बढ़ा लेंगे। हमारी जुड़ाव की नीति में मौलिक विसंगतियां हैं। प्रश्न अमेरिका और चीन के बीच चयन का नहीं है। प्रश्न अपनी स्वयं की ताकत को बढ़ाने का है। हमें अपनी बचत दर को बढ़ाना होगा, राष्ट्रीय विमर्श को आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता की तरफ मोड़ना होगा, व्यापार में मात्र जरूरी वस्तुओं का आयात करना होगा और आधुनिक तकनीकों में स्वयं निवेश करना होगा। इस दिशा में हमें चीन का ही उदाहरण देखना चाहिए। जिस प्रकार 80 और 90 के दशक में चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है उससे सबक लेने की जरूरत है। उस समय चीन की घरेलू बचत दर 45 प्रतिशत थी। आज हमारी बचत दर 25 प्रतिशत है। उस समय चीन ने अपने राष्ट्रीय विमर्श में आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी थी। उदाहरण के लिए नारा दिया कि 'अमीर होना अच्छा है।' आज हमारे राष्ट्रीय विमर्श में राम मंदिर, 1962 का युद्ध, कश्मीर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पाकिस्तान जैसे मसले दिखते हैं। उस समय चीन ने अमेरिका से विदेशी निवेश को आकर्षित किया और आधुनिक कमर्शल तकनीकें बाहर से हासिल कीं। लेकिन सामरिक तकनीकें खुद विकसित कीं। लड़ाकू विमान स्वयं बनाए। आज हम अमेरिका से गैर जरूरी माल जैसे अखरोट का आयात कर रहे हैं, अपनी आर्थिक नींव को कमजोर कर रहे हैं और सामरिक तकनीकों के लिए अमेरिका पर आश्रित हो गए हैं। हम अपने को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो अमेरिका और चीन के बीच पिसते ही रहेंगे।

अमेरिका के प्रभुत्व वाले क्वाड का उद्देश्य भी शेष तीनों देशों के हितों को साधने के लिए भारत का उपयोग करने का हो सकता है। क्वाड की ओर से भी तो भारत-चीन के सीमा विवाद को नहीं उठाया गया।

## क्वाड भी मौन

भरत झुनझुनवाला।।

अलास्का में हाल में हुई चीन से वार्ता में अमेरिका ने शिनजियांग, हांगकांग, साऊथ चाइना सी और ताइवान के मुद्दों को चीन के सामने उठाया। अमेरिका के राडार में भारत-चीन सीमा विवाद नहीं है। इससे साफ है कि अमेरिका जो भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है उसके पीछे मूलतः अपने हितों को साधने का मकसद है। उसका भारत के हितों से कोई संबंध नहीं है। कहा जा सकता है कि अमेरिका भारत को चीन के सामने मोहरे के रूप में खड़ा कर रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. नुरेल रोबिनी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच साझा लोकतांत्रिक संस्कृति है और दोनों देश स्वाभाविक मित्र हैं। लेकिन अमेरिका के सऊदी अरब जैसे गैर लोकतांत्रिक देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला जैसे लोकतांत्रिक देशों को अस्थिर करने को वह उद्यत है। रोबिनी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के क्वाड गठबंधन को भी महत्व दिया है।

अमेरिका के प्रभुत्व वाले क्वाड का उद्देश्य भी शेष तीनों देशों के हितों को साधने के लिए भारत का उपयोग करने का हो सकता है। क्वाड की ओर से भी तो भारत-चीन के सीमा विवाद को नहीं उठाया गया। चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में बंदरगाहों पर कब्जा किए जाने



को लेकर भी क्वाड उदासीन है। उसका ध्यान साउथ चाइना समुद्र पर है, न कि हिंद महासागर पर। ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत— इन चारों क्वाड देशों में केवल भारत ही ऐसा है जिसकी सरहद चीन से लगती है और इसी सरहद पर क्वाड मौन है। क्वाड के लिए भारत का इस्तेमाल कर हांगकांग, साऊथ चाइना समुद्र और ताइवान में अपने हितों को साधना आसान है। उसके लिए इसमें खास रिस्क भी नहीं है क्योंकि कीमत भारत चुकाएगा और फायदा क्वाड पाएगा।

अब तक भारत बहुकेंद्रीय विश्व की कल्पना में लगा हुआ था। गुटनिरपेक्ष संगठन इसका एक बड़ा जरिया हुआ करता था। लेकिन हकीकत यही है कि इस संगठन के सभी देश बड़े देशों के बीच पिसते रहे हैं और आज भी पिस रहे हैं। पूर्व में ये देश अमेरिका

और रूस के बीच पिसते थे, तो आज अमेरिका और चीन के बीच पिस रहे हैं। ऐसे में अगर भारत ने गुटनिरपेक्षता को छोड़कर अमेरिका का साथ अपनाया है तो यह एक तरह से ठीक ही है क्योंकि बदले दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो चुका है। परंतु दिक्कत यह है कि अमेरिका के पाले में बैठना कुएं से निकलकर खाई में गिरना है। गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत भारत दूसरे गुटनिरपेक्ष देशों के साथ पिस रहा था जबकि अमेरिका के पाले में बैठ कर भारत अकेले पिस रहा है।

ध्यान रहे, राजनीति में भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होता है। जब हम किसी देश से जुड़ते हैं तो वह जुड़ाव किसके पक्ष में काम करेगा या इस बात पर निर्भर करता है कि ताकतवर कौन है। मसलन, दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप में बड़ा पार्टनर ही जीतता है। भारत और अमेरिका के संदर्भ में देखें तो अमेरिका का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से हम उसके छोटे पार्टनर जैसे हो जाते हैं, और हमारा जुड़ाव अमेरिकी हितों को ही आगे बढ़ाता है। फिर भी अमेरिका के साथ जुड़ने में तात्कालिक लाभ यह है कि हमें सैन्य ज्वॉन और सैटलाइट तकनीकें मिल रही हैं। ये लाभप्रद हैं, बशर्ते हम इनका उपयोग अपने विवेक से अपने हितों को बढ़ाने के लिए करें, न कि चीन के विरुद्ध क्वाड के हितों को बढ़ाने के लिए।

यूटोको बवाल-5382				* 5382 का बल			
		2				3	
	9		8		2	6	4
1			3	6			9
4	3						
	8		2				1
						8	6
	4		7	5			3
3	7	5		4		1	
2						8	

### अपना ब्लॉग

### राजनीति का मुद्दा बन गया

मोहन। लोगों को प्रदूषण के बजाय सरकारों को वोट बैंक की अधिक चिंता है। दिल्ली में प्रदूषण का मामला पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकारों के बीच राजनीति का मुद्दा बन गया है। पंजाब में सामने चुनाव है इस हालात में सरकार किसानों पर कड़े कदम नहीं उठा सकती है। कोई भी सरकार किसानों को नाराज कर जोखिम नहीं लेना चाहती है। वायु प्रदूषण पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली का हिस्सा सिर्फ पांच फीसदी है। इसके बावजूद फिर राजधानी में कोहरा छाया हुआ है। जबकि पीएम 10 का स्तर 320 के करीब और पीएम 2.5 का स्तर 160 के ऊपर दर्ज किया गया। फिर किसानों की पराली कितनी जबाबदेह है यह खुद समझ सकते हैं। दिल्ली की आबोहवा दमघोट हो चुकी है। सांस लेना भी मुश्किल हो चला है। कुछ साल पूर्व एक सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रदूषण की वजह से 40 फीसदी लोग दिल्ली में रहना नहीं चाहते।

